[Shri Ghulam Rasool Matto]

at the present rate of taxation, show a deficit of Rs. 8120 crores and after fresh taxation to Rs. 7484 crores. But the hon. Minister of Revenue and the hon. Minister of Expenditure are here. I shall request them that they should assure this country that this Budget deficit will, under no circumstances, be exceeded. If there is any proposal from any Ministry for enhancing grants and allocations, they should be asked why and how they want to make savings in other sectors. This is very important. Under no circumstances should the deficit be allowed to exceed. This must be scrupulously adhered to.

My last point is that our non-Plan expenditure has gone up very high. This is one of the main reasons why they should think in terms of freezing the non-Plan expenditure for the next year. Why should we not think that there should be no increase in the non-Plan expenditure next year? If we can think that there should be no fresh appointments and all that, we can think of freezing the non-Plan expenditure also. When the prices are so escalating, the non-Plan expenditure is bound to increase. So my request to the hon. Minister would be to consider freezing of non-Plan expenditure. Let us think that for two years we will have an expenditure freeze.

I was not prepared for the speech today. The hon. Minister may kindly consider whatever little observations I have made today and react to them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have made out very good points.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): You represent the whole of that side.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: These are the only points I could make today. I was not having the papers with me today. I have borrowed from Shri Verma the Budget speech. The Minister may kindly consider the points raised by me and in his reply may react to my suggestions. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

Increase in the Central Issue Prices of Wheat for the Public Distribution System and other Schemes

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): Sir, as the House is aware, the support price of wheat to be paid to the farmer in the coming rabi season was raised by the Government from Rs. 166 to Rs. 173 per quintal. This increase, which was higher than that of the last three years, was widely welcomed.

The Central Government also fixes the price of wheat issued from the Central Pool to the State Governments for distribution under the public distribution system and other related schemes. Consequent upon the Government's decision to increase the support price of wheat by Rs 7.00 per quintal, the Government have decided to refix the Central issue prices of wheat to absorb the increase in the support price and some related costs and to contain the food subsidy.

The revised Central issue prices of wheat will be as follows:—

(i) For the public distribution system, it will be Rs. 204 per quintal instead of the existing Rs. 195 per quintal; and

(ii) For the ITDP areas and tribal majority States, it will be Rs. 139 per quintal against the existing Rs. 130 per quintal and the consumer price will be Rs. 164 per quintal instead of Rs. 155 per quintal.

The price of wheat for open market sales will be Rs. 240 per quintal.

All these prices will be effective from 25th March, 1988.

6.00 P.M.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): It is most unjustified. It is nothing but loot.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, Mr. Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairmain, Sir, I think that the increase of Rs. 9/- per quintal in the public distribution system while only Rs. 7/- has been paid to the farmers is quite unjustified. Last year the farmers were paid Rs. 166/- and the issue price then was Rs. 204/- per quintal and there was an in-built profit of Rs. 38/-. Now, the farmers are not happy because they are not getting their due. But the Civil Supplies Department, in my opinion—the Minister may correct me if I am wrong—got at Rs. 166/- and gave it to the public at Rs. 204/- and they were making a profit of Rs. 38/-.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No. The issue price at that time was only Rs. 195/-.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: All right. Then they were having a profit of Rs. 29/-. As if that profit was not sufficient and, therefore, he had to raise it by another nine rupees and this has made the confusion worse confounded. Already they were making a profit of Rs. 29/- and now they are making a further profit of Rs. 2/-. I would like the Minister to clarify this and correct me if I am wrong.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, Mr. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो घोषणा की है इसके द्वारा जो उपभोक्ता है, जो उत्पादक है, दोनों को लूटने की योजना बनायी गयी है । सरकार ने बराबर इस बात का आश्वासन दिया है इस सदन में और उस सदन में भी कि किसान जो उत्पादक है उनको उनके उत्पादन का रेम्यूनरेटिव प्राइस, लाभप्रद मूल्य दिया जायेगा । जो विवरण प्रस्तुत किया गया है इसमें भी बताया गया है कि पिछले कुछ दिन पहले 7 रुपये की वृद्धि की गयी थी पर-क्विंटल किसान को देने के लिए । आज जो वृद्धि की गई है उसके हिसाब से देखा जाय तो खुले बाजार में गेहूं का भाव 240) रु० होगा, लेकिन सरकार की जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वहां पर आपने 9) रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की है । मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को आप 7) रु० दे रहे हैं और उपभोक्ता से 9) रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं । यह जो आप 2) रु० का लाभ लेना चाहते हैं, यह आप बिचौलियों को क्यों देने जा रहे हैं ? किसानो को आप यह लाभ क्यों नही दे रहे हैं ? जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए ।

आपने इस बात की घोषणा की है कि खुले बाजार मे गेहूं का मूल्य 240) रु० प्रति क्विंटल होगा । किसान को तो 173) रु० दे रहे है और खुले बाजार में गेहूं 240) रु० में बेच रहे है । इस प्रकार 67) रु० आप बिचौलियों को दे रहे है । उपभोक्ता से आप ज्यादा दाम लेंगे, किसानों को कम मूल्य देंगे और बिचौलियों को 67) रु० का लाभ देंगे तो इस नीति का समर्थन कौन करेगा ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करें । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि ट्रेंटेन्स पर खर्च होगा और दूसरी चीजों पर खर्च होगा । लेकिन आप यह 67) रु० की जो वृद्धि कर रहे है, इसमे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसानों को इससे लाभ नहीं होगा । आपकी यह नीति बिलकुल किसान विरोधी है, जन विरोधी है । यह आपकी लाभ की योजना नहीं है, इससे किसानों और गरीबों को कोई लाभ नही होगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार से विचार करें कि इसका लाभ किसानों को मिले, गरीब तबके को मिले, जो उपभोक्ता है, जो गेहूं इस्तेमाल करते हैं, उनको इसक लाभ मिलना चाहिए ।

श्री शंकर सिंह वाघेला (गुजरात) : वाइस चेयरमैन साहब, सरकार की जो नीति है वह समर्थन मूल्य देने की है । मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि उनकी इस समर्थन मूल्य वाली बात से मैं सहमत नही हूं । समर्थन मूल्य की जगह इसको प्रोत्साहन मूल्य कहा जाना चाहिए । जो मूल्य आप किसानों को देते है, उससे ज्यादा मूल्य उसको बाजार में मिलता है । आप उसको 2) रु० या 5) रु० देते है, लेकिन बाजार में उसको ज्यादा दाम मिलते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं का कास्ट आफ प्रोडक्शन सब स्टेट्स में एक जैसा नही है । पंजाब और हरियाणा में गेहूं का कास्ट आफ प्रोडक्शन जो है उसके मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात में दूसरा है क्योंकि वहां पर इरीगेशन सोर्सेज उतने नहीं हैं जितने पंजाब और हरियाणा में है । सब राज्यों में समर्थन मूल्य आप एक समान देते हैं । आपको हर राज्य की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकाल कर देखनी चाहिए और उसी हिसाब से समर्थन मूल्य देने चाहिए । जैसा मैंने कहा, इसको प्रोत्साहन मूल्य कहें तो उचित होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गवर्नमेन्ट कहती है कि यह गरीबों की हिमायती है । गरीबों और ट्राइबल लोगों से वोट मांगने के लिए आप बेशक अच्छी-अच्छी योजनाएं बनाइये, लेकिन इन योजनाओं से इन लोगों को कोई लाभ नही मिल रहा है . . . (व्यवधान) । इस टाइम तो गरीबों को मारा जा रहा है । कई राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, कई व्हीट इटर राज्य अकाल से ग्रस्त हैं । आपका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कितना काम कर रहा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । कई इलाकों में अनाज नही पहुंच पा रहा है । जिन मजदूरों को 11) रु० पहले मिल जाते थे वे भी अब उनको नही मिल पाएंगे । आपको चाहिए था कि आप अकालग्रस्त इलाकों मे ज्यादा सुविधाएं देते । आप ट्राइब्ल और गरीबों के हिमायती कहलाते हैं, आप क्यों नहीं कोई परमानेन्ट व्यवस्था करते है जिससे इन गरीबों को रोजगार मिल सके और इन राज्यों को सुविधाएं मिल सक । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप समर्थन मूल्य के बजाय इसको प्रोत्साहन मूल्य दीजिये । जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है उसको आप प्रत्येक राज्यों में वहां की लागत को देखकर निश्चित कीजिये । जनता पार्टी के समय हमारे गुजरात राज्य में किसानों के लिए भाव बढ़ा दिये गये थे । राज्यों की कास्ट आफ प्रोडक्शन को देखकर समर्थन मूल्य होना चाहिए । जो बातें मैंने उठाई हैं उनके संबंध में माननीय मंत्री जी कुछ बातें हमें बताएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है ।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, we have just heard from the hon. Minister that the issue price for wheat for the coming year has been increased. Now, last year also we had heard from the Minister a similar statement. But these issue prices are not in consonance with the reality because the production cost is high and they don't get remunerative prices. We may call the prices remunerative. But the price as declared here is not remunerative. Moreover, the pricing policy of the Government actually helps the monopolist traders. For example, the price of wheat in the open market will be Rs. 240/- per quintal. So, you have declared a price of Rs. 240/- while the market price is already much higher. The Statesman of today states that the wheat dara, kalyan and desi varies cost Rs. 225 to Rs. 250, Rs. 255/- to Rs. 260 and Rs. 270 to Rs. 340 per quintal respectively. Who is going to control the open market? Salary earners, wage earners common people and the peasants who produce foodgrains are being fleeced by these monopoly traders like anything. The Government policy is going to encourage them. There is not a single word about them. Good words are not sufficient. It depends on whether the Government has got an effective distribution system in the tribal areas as well as in other areas. The present distribution system in the rural areas, which is know as 'modified rationing system', is absolutely worthless and ineffective and is in the hands of traders and *arathdars* who are going to control the market. The Government machinery is

not going to control them. But the Government machinery actually helps them.

There is statutory rationing in the urban areas and in the industrial areas. There also there is meagre and bad quality supply of wheat and it helps the traders who fleece the people in the open market. There is no coordination between the Government's declared policy and the ruling prices in the market. In the past also you have increased the support price of wheat. The percentage of increase in the support price of wheat during the last four years, i.e. from 1985-86 to 1988-89, has been surpassed by the issue price that you have declared. So, you have no policy to safeguard the interests of the peasants and the producers. You have no policy to safeguard the interests of the urban consumers. You have no policy to safeguard the interests of the tribals and of the people who are below the poverty line. So, we want from you a definite assurance that you will develop an all-India system of common distribution at a unified price, at a common price. Unless it is done, unless the entire distribution system is taken up by the Government, controlled by it in the interest of the people and you declare a price policy which is in the interests of peasants and consumers, there will be no help for the peasants, workers and consumers. Hence the policy declared is merely an eye-wash. It will actually help the monopoly traders and not the peasants and the workers. Therefore, Sir, I request the Government to revise the policy, review it and adopt a popular policy in the interests of the peasantry, in the interests of the workers and in the interests of consumers as well. With these words, Sir, I conclude.

SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA (Andhra Pradesh): Sir, the Minister has revealed the support price as well as the distribution price but I could not understand how this support price has been arrived at. The other day the Agriculture Minister declared Rs. 172 per quintal and here the Food and Civil Supplies Minister raises the price of wheat in public distribution system and in the open market. What I feel is that there is no coordination between the two Ministries. The other day we questioned the Agriculture Minister, Mr. Yogendra Makwana how this Rs. 173 per quintal has been arrived at whether the cost of cultivation had been calculated and we asked him about break-up and I want to know the same thing from the Minister of Food and Civil Supplies also. I want to know how he has arrived at Rs. 204 for public distribution system and Rs. 240 for sale in the open market. It seems there are buffer stocks in the country and are you going to operate this scheme for oil released from the buffer stocks? One more point. Under NREP and RLEGP foodgrains wheat is given through out the country. I want to know what will be the Government rate for this wheat under NREP and RLEGP.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : किसान जो पैदा करता है उसके उत्पाद का जो मूल्य मिलता है और उसको बेच कर जो अपनी आवश्यकता की वस्तुऐं खरीदता है निरन्तर प्रति वर्ष किसान घाटे में जा रहा है। हम लोगों को निरन्तर यह शिकायत है कि किसान को लाभप्रद कीमत नहीं मिलती है । एक तरफ यह शिकायत है कि सात रुपए बढ़ाए हैं जिसे हम लाभप्रद नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ता को 31 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को भी अधिक देना पड़ेगा और किसान को कम कीमत मिलेगी और फिर दो हजार करोड़ रुपया आप सबसिडी का भी बताते हैं खाद्यान्न पर आप सबसिडी और दे रहे है। माननीय मंत्री जी मुझे हमेशा यह शिकायत रही है उपभोक्ता को कौन-सी सबसिडी मिल रही है ? आपने आई० टी० डी० पी० एरिया में और ट्राइबल एरिया मैजोरिटी स्टेट्स को आपने सबसिडी दी है यह समझ आने वाली बात है इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और उन एरियाज में आप 164 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उपभोक्ताओं को देंगे लेकिन किन उपभोक्ताओं को आप 164 रुपए के हिसाब

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

से देंगे यह भी आप बताने की कृपा करें। आई० टी० डी० पी० एरिया में ट्राइबल एरियाज में आपने जो सबसिडी दी है इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं लेकिन शेष देश के उपभोक्ताओं को आपने 31 रूपए फालतू पर दिया । यह जो दो हजार करोड़ रुपए की सबसिडी है जो आप कहते है तो क्या यह आपका एफ० सी० आई० का जो इतना बड़ा घाटा है जो उसमें चोरियां होती हैं, भ्रष्टाचार है, जो उसके रख-रखाव में खर्च में गड़बड़ियां हैं क्या सारा का सारा दो हजार करोड़ रुपया एफ० सी० आई० में तो नहीं जा रहा है ? आप प्राइवेट ट्रेड को देखिए मैं प्राइवेट ट्रेड के पक्ष में नहीं हूं लेकिन इसका मतलब यह नही है कि एफ० सी० आई० भी उसी तरह से करें जिस तरह से आपकी दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कर रही हैं । मैं कल बजट पर बोलूंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके से पब्लिक अंडरटेकिंगज का नुकसान बढ़ रहा है और किस हिसाब से जो टाप के बड़े 20 आदमी हैं वह अपना मुनाफा तेजी से बढ़ाते चले जा रहे है ।

मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि यह बताने की कृपा करें कि दो हजार करोड़ रुपए की जो सबसिडी आप देते हैं उसे किस प्रकार करेंगे ? 173 में अगर सबसिडीज करते तो समझ में आता कि 150 या 130 में का कंज्यूमर को फायदा पहुंचा । 31 रुपए फालतू लिए तो सबसिडी कैसे हुई ? फिर आप कंज्यूमर को कैसे 240 रुपए पर । आपने भी बिल्कुल बनिये की दुकान खोल ली । क्या जरूरत थी इस दुकान को खोलने की । अगर फ्लोर मिल को लेना है जिसको 240 पर देंगे तो वे खुले मारकेट से ले सकते है, आप क्यो देते है ? इसका मतलब यह है कि आप इसमें मुनाफा कमायेंगे । यह आप किसान को दें या उपभोक्ता का लाभ करे ।

तीसरा इसके बीच में चाहे एफ० सी० आई० खाये चाहे गवर्नमेंट खाये यह बीच में मुनाफा खाना सर्वथा निंदनीय है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप बिचोलियों के खिलाफ हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : बनिए बन रहे हैं । इसलिए आप बताने की कृपा करें कि किस प्रकार आप उपभोक्ता की सेवा कर रहे हैं और उसको फायदा पहुचा रहे हैं ?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is a welcome measure. The Government has increased the support price for the farmers from Rs. 166 to Rs. 173...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: It was done about 7 months back.

SHRI V. NARAYANASAMY: The features which I find here are, while giving an increase of Rs. 7 to farmers, there is increase of Rs. 9 in the distribution system which has been given to ITDP areas and tribal areas. While the price was increased from Rs. 130 to Rs. 139, and again from Rs. 155 to Rs. 164, I am not able to understand why you are giving only Rs. 7 increase to the farmers. Secondly, I want to know as to what will be the total amount which we are going to get out of this increase in price relating to public distribution system. Thirdly, there is one system which prevails in the country, about which I would like to ask the hon. Minister. And that is about the commission agency system. The Ministry of Food and Civil Supplies, especially the FCI is encouraging private commission agents. In Haryana alone, the Government is giving about Rs. 30 to Rs. 50 crores to the commission agents. Thus, the Government itself is encouraging private traders, private persons who are dealing in commission agency and this system of commission agents prevails in many other parts of the country.

I would like to know from the hon. Minister as to why the FCI is paying more than Rs. 50 crores to them in Haryana alone. You have got all the paraphernalia of the FCI. I am not able to understand why should you spend so much money on the commission agents. That money can be very well utilised for the

purpose of giving benefits to people in tribal areas, to people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

I would like to know from the hon. Minister what will be the amount he will earn by this increase and how you give Rs. 7 only to farmers.

श्री सुख राम : महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने जो यहां पर कुछ सुझाव दिये, कुछ चिंताएं व्यक्त की, कुछ शिकायतें की, मैं उन सबों का आभारी हूं और कुछ उनके जो भ्रम है उन भ्रमों को दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इस माननीय सदन में सब तरफ से एक आवाज आती है कि कृषकों को ठीक मूल्य मिलना चाहिये और इस सरकार ने यह जो प्रोक्योरमेंट की पालिसी, बफर स्टाक मेन्टेन करने की पालिसी अख्तियार की है इसके माध्यम से जो कृषक है उनके लिये कम से कम मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। और यह भी फसल बीजने से पहले, ताकि उसको मालूम हो कि उसकी पैदावार का कितना उसको लाभ मिलेगा और उसके मुताबिक वह अपनी फसल का इंतजाम करे इसमें भी यह है कि सी०ए०सी०पी० की सिफारिश के मुताबिक...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी ने कम से कम मूल्य कहा।

श्री सुख राम : आप जरा सुनने की कृपा करें। सी०ए०सी०पी० एक एक्सपर्ट बाडी है, जो यह देखती है कि उत्पादक का कितना खर्चा पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की राय ली जाती है और उसके मुताबिक उनकी सिफारिश आती है, जिसको केंद्रीय सरकार माने, उसमें कमी करें, बढ़ोतरी करें। आम पौर पर वह मानी जाती है। कभी-कभी उसमे बढ़ोतरी भी होती है।

तो प्रश्न यह है कि एक तरफ तो कृषकों की चिंता है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की भी चिन्ता है अगर इसका समन्वय हम करें, कोई बीच का रास्ता निकालने की बात करें, तो सरकार ने उसके लिये एक बीच का रास्ता निकाला है, जो मिनिमम कीमत है। मगर उसमें जो सपोर्ट प्राईस है, उसमें उसका जितना खर्चा है और उसमें जितना लाभ है, प्राफिट है, इन्सेंटिव है, वह भी उसमें शामिल है, तब जाकर वह कीमत फिक्स होती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो स्टेट-वाईज होना चाहिये। यह मुमकिन नहीं है, यह बात व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जो बफर-स्टाक में अनाज ज्यादा मिलता है, तकरीबन 75-80 प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो सारे देश में अगर हम स्टेट-वाईज इसको निकालने की कोशिश करें तो यह मुमकिन नहीं है। इस वास्ते एक एवरेज लेकर के वह मूल्य निर्धारित करते हैं और उस मूल्य को निर्धारित करने के बाद—अब प्रश्न एक और है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है-पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को अगर देखा जाए, तो वह कमजोर वर्ग के लिये है, या मध्यम वर्ग को उसमे शामिल कर लिया जाए, तो गरीब आदमी जो उसमें शामिल कर लिया जाए, उसके लिये है। मगर आज जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसमें सारे देश के लोग आज शामिल हैं और हम अगर यह करें कि उसको महज उसी वर्ग तक सीमित रखें, तो फिर जो किसान सरप्लस पैदा करेगा, उसको हम खरीदेंगे, अपने भंडार में रखेंगे, तो उस भंडार से वह निकलना भी चाहिए, स्टेट्स को मिलना चाहिए। अगर हम उसी आबादी तक

[श्री सुख राम]

सीमित रखें, तो हमारे पास जो सरप्लस है, उसका क्या करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में हम जाएं, क्योंकि कास्ट आफ प्रोडक्शन बाकी देशों की निस्बत हमारा ज्यादा है, इस वास्ते हम वहां भी कम्पीट नहीं कर पायेंगे। कम्पीट करेंगे, तो उसके वास्ते आपको सबसिडी देनी पड़ेगी--इस वास्ते कि वह मुमकिन नहीं है।

अब मैं तो वकिंग समझता था कि माननीय सदस्य सरकार को बधाई देंगे कि उसने इन वर्षों में सब से ज्यादा इस बार सात रुपये प्रति क्विंटल किसानों को इसमें कीमत दी है।...

श्री शंकर सिंह वाघेला : आपने जब से समर्थन मूल्य की पालिसी अपनाई है, तब से बाजार की कीमत और आपकी कीमत में क्या कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि कार्पोरेशन में जब प्राईस गिरती है, तो कोई खरीदने वाला नहीं होता है।

श्री सुख राम : अगर आप निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, अगर पार्टी पालिटिक्स को बीच में लायेंगे, तब तो आप किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकेंगे।... (व्यवधान)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जनता का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री सुख राम : अगर आप निष्पक्ष भाव से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरकार ने जो नीति अपनाई है, वह बिलकुल सही है, कृषकों के पक्ष में भी है और उपभोक्ताओं के पक्ष में भी है। और उसकी वजह है, अभी कुछ माननीय सदस्य चले गए, तो वह कर लिया कि हम 173 रुपये में उसको समर्थन मूल्य देते हैं और 204 रुपये में बेचते हैं, बीच का वह नफा में आ गया, यह जितना आपका जो फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया है...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : कुछ चले गए नहीं यहां बैठे हैं, मटटू जी सुनिए।

श्री सुख राम : क्योंकि जितना रुपया ज्यादा से ज्यादा जो कि फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रोक्योरमेंट के लिए लगाती है वह फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंज से लोन लेती है जो 14 प्रतिशत उसमें वह इन्टरेस्ट का देना पड़ता है। उसके साथ-साथ जो उसमें प्रोक्योरमेंट की कास्ट है, कहां उत्तरी भारत से जो 80 प्रतिशत करीबन अनाज बफर स्टाक के लिए इस हिस्से से जो इक्टठा करते हैं यहां का खर्चा और फिर ट्रेन से उसको तामिलनाडु तक पहुंचाना, आन्ध्र तक पहुंचाना, कलकत्ता तक पहुंचाना, महाराष्ट्र तक पहुंचाना, कितना बड़ा यह काम है और कितना बड़ा इसमें खर्चा है। तो इसमें अगर इकोनोमिक कास्ट देखी जाए तो वह 100 रुपए से ऊपर बैठती है और उसमें जो कंज्यूमर सबसिडी है वह करीब 103 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। उसमें अगर देखिए तो जो कैरिंग कास्ट है जो आप गोदाम वगैरह में जितना अनाज रखते हैं उसकी कैरिंग कास्ट 1987-88 में 37.24 रुपये पर क्विंटल है और जो सबसिडी जो कि इंसीडेन्टल चार्जेज हैं, जो खर्चे पड़ते हैं ऊपर के 76.64 रुपये प्रति क्विंटल और इस तरह से करीबन 103/- रुपया यह खर्चा प्रति क्विंटल आता है। ...(व्यवधान) जो आप सुझाव देंगे और वर्मा जी को मेरा निमन्त्रण है, आप सुझाव देंगे और अगर कहीं ज्यादा खर्चा है, नाजायज खर्चा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस खर्चे को रोकूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि 173 तो आपकी लागत है और 103 आपका खर्च है तो हुआ 276. why are you selling at Rs. 214?

श्री सुख राम : 240 में भी ऐसा है और इसमें एक बात और है.... (व्यवधान)

SHRI SUNIL BASU RAY: One more point has to be clarified. When the Railway Minister claims that he is carrying the food articles at concessional rate, why is the Finance Minister charging 14 per cent interest like Shylock? What is the common link between the two policies? This has to be clarified.

श्री सुख राम : यह तो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बफर स्टाक की जो हमारी पालिसी है उससे मार्केट में कीमत बरकरार रहे, ठीक रहे, मुनासिब रहे और उप सभाध्यक्ष जी, मैं एक बात दावे से, अगर आप भी इस बात को समझते हैं ...(व्यवधान) आपने कहा कि यह तो आप इसकी इकट्ठा करते हैं अनाज उसमें ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और यह बफर स्टाक अगर न होता तो अब की बार जितना यह सूखा पड़ा और फूड्स में हमने करीबन 22 प्रतिशत पहले से ज्यादा राज्यों को अनाज दिया पिछले साल के मुकाबले में ड्राउट और उसके लिए यह कहां से देते और प्राइस मैनटेन रही अगर यह बफर स्टाक से अनाज पी० डी० एल० में न देते और अभी आपने आई० टी० डी० पी० की बात कही करीबन दो मिलियन टन अनाज हमने सारे देश को इसमें दिया एक रुपया तीस पैसे प्रति किलो, 130/- रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, आप बोलिये मार्केट में कितनी कीमत थी और क्या कभी गरीब लोगों को इतना मिल सकता था ? और पी० डी० एस० में हमने दिया, यह 195/- रुपए में दिया, जबकि मार्केट में कीमत उससे ज्यादा थी यह जो फ्लोर मिल हैं, इनको हम 210/- रुपए में देते थे, इसको 240/- रुपए में दिया है। मगर इसमें भी अभी तक सबसिडी का एलीमेंट है । हम यह कोई कामर्शियल रेट पर नहीं दे रहे हैं। ओपेन मार्केट में इसलिए दे रहे हैं ताकि जो मार्केट में दे रहे हैं, पी० डी० एस० में दे रहे हैं और ओपेन मार्केट में इसलिए दे रहे हैं ताकि जो ब्लैकमार्केटियर हैं, होर्डिंग करने वाले लोग हैं, वे अनाज की होर्डिंग करके उसकी ज्यादा कीमत न कर दें। इस वास्ते उसको देते हैं । इस वास्ते जो पावर्टी एबालीशन प्रोग्राम है, उसमें दो मिलियन टन बल्कि 22 लाख टन अनाज हमने इसमें दिया । अगर यह सारा भण्डार हमारे पास न होता तो बड़ी मुश्किल आती । आपने कहा–7/- रुपए, हमने 7/- रुपए दे दिया, उसका तो ठीक है, आपने तारीफ नहीं की चलिए कोई बात नहीं

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैंने कम बताया ...(व्यवधान)

श्री सुख राम : कम बताया, मगर आप एक बात तो सोच लें, 2,000 करोड़ रुपया महज अनाज के ऊपर आज सरकार सबसिडी दे रही है, अगले वर्ष 2300 करोड़ हो जाएगा । इस तरह से बढ़ेगी । आप एक बात का अंदाजा लगायें कि आपके पास किटी है, उस किटी से आप सबसिडी ज्यादा दे दीजिये, तो आपका उतना और कम रुपया हो जाएगा इस देश के निर्माण के लिए । इस लिए हमारी चिन्ता यह भी है कि हम किस तरह से इस सबसिडी को कंटेन रखें । अब यह जो 7/- रुपया बढ़ाया है, आपने कहा कि 9/- रुपया बढा दिया है, जबकि 7/- रुपए हैं, मण्डी चार्जेज, परचेज सेल्स टैक्स वगैहरा जो 10 फीसदी के हिसाब से हैं, यह 7/- रुपए की बढ़ोतरी इसमें 10/-पैसे की बढ़ोतरी होगी और जो इंटरेस्ट है, जितना रुपया अब आपने ज्यादा रखा, उसमें खर्चा करना पड़ेगा और उसके इंटरेस्ट का 1.08 रुपया जो है, यह इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होगी यानी उसमें आपका 8.70 रुपया इंसीडेंटल खर्चा होगा और उसमें राउन्ड आफ करके 9/- रुपया कर दिया । अगर आप उसको न करें तो यह जो 2,000 करोड़ रुपया सबसिडी दे रहे हैं, यह उससे और बढ़ जाएगा ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Because you have reduced stocks, your net interest payment will come down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It will come down now.

श्री सुख राम : तो मैं आपसे यह कह रहा था कि इसमें कोई सरकार के लिए मुनाफे की बात नहीं है, कोई कमाई नहीं है । हम यह चाहते हैं, और यह जो आप कहते हैं, यह तो लूट है, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस माननीय सदन में इतने जिम्मेदार होते हुए ऐसी बात कहे। कांग्रेस सरकार ने तो हमेंशा से ही कृषकों का पक्ष सबसे ऊंचा रखा है । मैं जानता हूं आपने जनता पार्टी की बात

सुख राम]

की, वह 77 से 80 तक क्या करती रही ... (व्यवधान)... यह तो आपने सत्यानाश कर दिया था किसानों का उस समय । यह तो हमने आकर फिर ठीक किया और तब जाकर आज उपभोक्ताओं को ठीक दाम से अनाज मिल रहा है इस देश में । यह कांग्रेस सरकार की वजह से, हमारी नीतियों की वजह से है । ... (व्यवधान) ...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आपने किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं किया ? इसलिए आज किसानों का आन्दोलन चल रहा है । ...(व्यवधान) ...

श्री सुख राम : वह किसानों का आन्दोलन राजनीति से प्रेरित है । ... (व्यवधान) ... अगर वह राजनीति से प्रेरित न होता तो यह सारे हिन्दुस्तान में फैलता, मगर एक पाकेट यू० पी० में ही यह सीमित रहा । यह बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है । ...(व्यवधान)... जो किसानों को इस सरकार ने दिया है, आपकी सरकार ने नहीं दिया । इस वास्ते उपसभाध्यक्ष जी मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि यह जो वृद्धि हुई है यह किसानों के हक में भी है, उपभोक्ताओं के हक में है और देश के हक में भी है । उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हम कभी एक क्विंटल अनाज अब तक बाहर से नहीं लाए । हमने अपने साधनों से इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला किया है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि आपने यहां जो प्रश्न रखे हैं ... (व्यवधान) ...

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Mr. Vice-Chairman, Sir, I want a small clarification. Regarding buffer-stocks I have spoken about it the other day. If we did not have the buffer-stocks, we would have had many starvation deaths. I would ask the hon. Minister even after making Rs. 29 per quintal in the public distribution system and Rs. 67 in the free sale, in spite of that, there is a subsidy of Rs. 2300 crores.

THE VICE-CHARMAN (SHRI JAGESH DESAI): He said Rs. 103 per quintal.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: In spite of that...

श्री सुख राम : मटट् जी मैं आपको निमंत्रण देता हूं और कोई भी दूसरे माननीय सदस्य जो भी मुझको सुझाव देंगे हम उन पर ध्यान देंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जरूर देंगे ।

श्री सुख राम : यह जितनी इकोनोमिक कास्ट आती है इसमें कमी हो अगर आप कोई सुझाव देते हैं और हम देखते हैं कि वह ठीक बैठता है तो हम उन पर ध्यान देंगे । तो मैंने आपको बताया इस तरह से ये सारे खर्चे हैं । वह तो सारा लंबा हिसाब है । उसको यहां बता पाना संभव नहीं है । उसे तो बैठकर ही बताया जा सकता है ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Are you not reducing your subsidy per unit, per quintal? Can you answer?

SHRI SUKH RAM: In that case the subsidy amount will considerably increase from Rs. 2000 crores to I do not know what will be amount. It may be much more. It is not possible.

श्री सुख राम : उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक ही बात कहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो सपोर्ट प्राइस है यह पापुलर होनी चाहिए यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होनी चाहिए । हम तो पापुलिस्ट्स सरकारों की जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ हैं । हम पापुलिस्ट नहीं चाहते । पापुलर भले ही हो और मिनिमम हो जोकि सब के हित के लिए ठीक हो ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, the House stands adjourned and will again meet on 22nd March, 1988, at 11.00 A.M.

The House then adjourned at fourty-four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 22nd March, 1988.